



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 567]
No. 567]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 1984/कार्तिक 29, 1906
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 20, 1984/KARTIKA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1984

का० आ० 887(अ) :—केन्द्रीय सरकार की राय है कि सार्वजनिक
महत्व के एक निश्चित मामले, अर्थात् 31 अक्टूबर, 1984 को श्रीमती
इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, की हत्या की जांच करने के प्रयोजन के
लिये एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952
का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
के उच्चतम न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री एम०पी०
ठाकुर, को अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त करती है।

2. आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा :—

- (क) पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारण बनने वाली घटनाओं का
क्रम और इससे संबंधित सभी तथ्य ;
- (ख) क्या इस अपराध को रोका जा सकता था और क्या अपराध
होने के समय सुरक्षा इयूटी पर तैनात व्यक्तियों में से किसी
व्यक्ति और पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी
अथवा व्यक्तियों की ओर से इस बारे में उनके कर्तव्य में कोई
त्रुटि या अवहेलना की गई ;

(ग) सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था में, जैसी कि विहित है या
व्यवहार में प्रचलित है, कोई कमियां, जिनसे इस अपराध को
करना सरल हो गया हो ;

(घ) अपराध किये जाने के पश्चात् स्वर्गीय प्रधानमंत्री की परिचर्या
करने, और चिकित्सीय परिचर्या की व्यवस्था करने, के बारे में
प्रक्रिया और उपायों में, जैसे कि विहित है, या व्यवहार में
प्रचलित है, कोई कमियां, और क्या इस तरह की चिकित्सीय
परिचर्या की व्यवस्था करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों की
ओर से इस बाबत कर्तव्य में कोई त्रुटि या अवहेलना की गई ;

(ङ) क्या इस हत्या का विचार बनाने, इसके लिये तैयारी करने
और इसकी योजना बनाने के लिये एक या अधिक व्यक्ति
या अभिकरण उत्तरदायी थे और क्या इस संबंध में कोई
पड़ोस था, और यदि हां, तो उसका सम्पूर्ण स्वरूप।

3. आयोग ऐसे सुझावों उपायों और कार्रवाहियों की सिफारिश भी
कर सकेगा जिन्हें ऊपर पैरा 2 के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट विषयों के
संबंध में अधिष्ठाता में करना आवश्यक हो।

4. आयोग अपनी रिपोर्ट, केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र, किन्तु 6
मास के पश्चात्, प्रस्तुत करेगा।

5. यदि आयोग, ठीक समयसे तो, यह पैरा 2 में वर्णित विषयों में से
किसी भी विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उपरोक्त
समय से पहले दे सकेगा।

6. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. वेन्द सरकार की यह राय है कि, जो आने वाली जाच के स्वतन्त्र और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 62) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू किये जाने चाहिये, और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्देश देती है कि उस धारा की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबन्ध आयोग को लागू होंगे।

[सं. 1/12014/75/84-आई एफ (डी-III)]

प्रेम कुमार, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1984

S.O. 867(F).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the assassination of Smt. Indira Gandhi, the late Prime Minister, on the 31st October, 1984.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry to be presided over by Justice M.P. Thakkar, a sitting Judge of the Supreme Court of India.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters:—

- (a) the sequence of events leading to, and all the facts relating to, the assassination of the late Prime Minister;
- (b) whether the crime could have been averted and whether there were any lapses or dereliction of duty in this regard on the part of any of the individuals on security duty at the time of the commission of the crime and other individuals responsible for the security of the late Prime Minister;

(c) the deficiencies, if any, in the security system and arrangements as prescribed or as operated in practice which might have facilitated the commission of the crime;

(d) the deficiencies, if any, in the procedures and measures as prescribed, or as operated in practice in attending to, and providing medical attention to the late Prime Minister after the commission of crime; and whether there was any lapse or dereliction of duty in this regard on the part of individuals responsible for providing such medical attention;

(e) whether any person or persons or agencies were responsible for conceiving, preparing and planning the assassination and whether there was any conspiracy in this behalf and, if so, all its ramifications.

3. The Commission may also recommend the corrective remedies and measures that need to be taken for the future with respect to the matters specified in clause (d) of para 2 above.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 6 months.

5. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2.

6. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

7. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2) sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. 1/12014/75/84-IS(D-III)]

PREM KUMAR, Home Secretary